Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

7वां सप्रु हाउस व्याख्यान

द्वारा

महामहिम श्री माधव कुमार नेपाल

नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री

विषय

"नेपाल में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और आगामी संविधान सभा चुनाव"

स्थान
सप्रु हाउस, नई दिल्ली

26 जुलाई, 2013

महामहिम सभापति, महानिदेशक, आईसीडब्लूए, शिक्षाविद और बुद्धिजीवी, अतिविशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों

मेरे लिए यह खुशी की बात है कि मुझे इस प्रमुख संस्था , विश्व मामलों की भारतीय परिषद् (आईसीडब्लूए) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस परिषद् का महत्वपूर्ण और विषयगत मुद्दों पर वाद-विवाद , चर्चाओं और बातचीत को आयोजित व बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक मंच का लंबा अस्तित्व रहा है जिनकी संपूर्ण विश्व में भरपूर मान्यता है और इसकी सराहना की जाती है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि विभिन्न क्षेत्रों पर सभी प्रकार के सुविज्ञ विचार-विमर्श और चर्चाओं से व्यावहारिक नीतियों के निरूपण में नीति निर्धारकों को बहुमूल्य सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मैं इस अवसर पर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपके सतत जुड़ाव और योगदान के लिए आईसीडब्लूए में आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समय निकालने हेतु प्रबुद्ध श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत देव मुखर्जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।

इन दिनों मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के आमंत्रण पर भारत के सरकारी दौरे पर हूं। इस ऐतिहासिक और सुन्दर शहर में आगमन पर मेरा भव्य स्वागत किया गया है। मैं इसे नेपाल और भारत की सरकारों और लोगों के बीच गहरे और निकट संबंधों के प्रतिबिंब के रूप में देखता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार को मुझे और मेरी टीम को आमंत्रित करने व आतिथ्य सत्कार किए जाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

जैसा कि आप जानते हैं , मैं मई, 2009 से फरवरी , 2011 तक नेपाल का प्रधानमंत्री था। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में मैंने अगस्त , 2009 में भारत का सरकारी दौरा किया था। मुझे भारतीय नेतृत्व के साथ बैठकें , और अपने द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को विस्तार देने व मजबूत करने के लिए जो हमने समझ विकसित की है , स्पष्ट रूप से स्मरण है। हम अपने परस्पर हित के मुद्दों से अवगत हैं , और साथ ही एक दूसरे की वैध चिंताओं व संवेदनाओं को भी समझते हैं। मैं महसूस करता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी यात्रा के दौरान जिन मुद्दों पर हमने चर्चा की , वे मुद्दे आज भी संगत हैं , और हमें नेपाल-भारत संबंध संबंधी परस्पर समझ और सहयोग को नयी ऊंचाई तक ले जाने के लिए इन पर परिश्रम करना पड़ेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने समानता , परस्पर सम्मान और सहयोग के आधार पर नेपाल-भारत के संबंधों में सुधार करने, विस्तार करने और मजबूत करने के लिए बेहतर प्रयास किया। नेपाल-भारत संबंध को

गर्मजोशी भाईचारे, सद्भावना, परस्पर समझ और सहयोग के लिए जाना जाता है ; साथ ही; हमारे लोगों के बीच निकट संबंध व आदान-प्रदान हमारी सरकारों के बीच मजबूती के सबसे बड़े स्रोत के रूप में स्मरण कराता है।

आज सुबह मैं नेपाल की विदेश नीति के व्यापक संदर्भ में नेपाल-भारत संबंधों के बारे में बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी नेपाल-भारत के संबंधों से अवगत हैं , मैं इसे आवश्यक नहीं मानता हूं कि यह इस मामले पर अधिक बोला जाए। बल्कि मैं आपको नेपाल में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम , संविधान सभा हेतु चुनाव की तैयारी के बारे में अद्यतन जानकारी देना चाहूंगा और साथ ही इस चुनाव और कुछ अन्य मुद्दों पर अपनी पार्टी की स्थिति के बारे में सूचि करना चाहूंगा।

नेपाल और भारत के बीच बेहतरीन द्विपक्षीय और निकट संबंध एवं बहुआयामी संधि है। यह संबंध प्राचीन ऐतिहासिक संबंध, संस्कृति, परंपरा और धर्म से और मजबूत हुआ है और यह एक दूसरे की सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के समाधान में अधिक स्पष्ट हुआ है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व , संप्रभु समानताएवं एक-दूसरे की आकांक्षाओं व हितों की समझ के सिद्धांतों के प्रति हमारी अटल प्रतिबद्धता हमारे संबंधों का आधार रही है। अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्द्रपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने और बढ़ाने के की नेपाल की गंभीर इच्छा के अनुसरण में यह भारत सहित अपने पड़ोसी देशों के विरूद्ध किसी विद्वेषपूर्ण तत्वों द्वारा अपने भूभाग का इस्तेमाल नहीं करने देने की अपने दीर्घकालिक रूख का अनुसरण कर रहा है और साथ यह अपने पड़ोसी देशों से यही आश्वासन की आशा करता है। भारत सरकार , भारतीय राजनीतिक दल और भारत के लोगों ने नेपाल में पूर्ण लोकतंत्र की पुनर्बहाली के लिए अप्रैल , 2006 के शांतिपूर्ण जन आंदोलन का पूरजोर समर्थन किया है। भारत सरकार ने अंतरिम संविधान के प्रख्यान और 15 जनवरी , 2007 को नेपाल में अंतरिम विधानमंडल के गठन , 10 अप्रैल, 2008 को नेपाल में संविधान सभा के चुनाव और शांति प्रक्रिया और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों का स्वागत किया है।

नेपाल-भारत संबंधों के बारे में बात करते हुए हम इस समझ पर पहुंचे हैं कि हमें कुछ नए क्षेत्रों में साथ मिलकर कार्य करना है। लगातार वर्षा और बाढ़ से उत्पन्न नेपाल के पश्चिमी भाग और भारत के उत्तराखंड में हाल की प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप जान और माल का व्यापक नुकसान हुआ है। इस आपदा में नेपाल और भारत दोनों देशों के नागरिकों की जानें गयीं , शायद अन्य देशों के लोगों की भी जानें गयीं। हमने उन मृतकों की राष्ट्रीयता के निरपेक्ष जान-माल के नुकसान पर गंभीर दु:ख प्रकट किया है और पीड़ित परिवारों को अपनी शोक संवेदना भेजी है। हमने भारतीय प्राधिकारियों द्वारा उत्तराखंड में नेपाली नागरिकों के बचाव और पुनर्वास की भी

सराहना की है। इन आपदाओं ने भी जलवायु परिवर्तन जैसे नए क्षेत्रों में साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता का हमें स्पष्ट रूप से स्मरण कराया है। मैं आश्वस्त हूं कि हमारी सरकारें इस वास्तविकता पर ध्यान देगी और अर्थपूर्ण तरीके से साथ मिलकर कार्य करना शुरू करेगी।

अतिविशिष्ट प्रतिभागी,

जैसा कि आप जानते हैं, अप्रैल, 2006 के लोकप्रिय विद्रोह के बाद नेपाल लंबे संक्रमण काल से गुजर रहा है। हम एक दशक से कम समय में ही दूसरी संविधान सभा के लिए चुनाव कराने के दहलीज पर हैं।यह प्रथम चुनी हुई निकाय द्वारा इस विद्रोह के दौरान व्यक्त लोगों की जनवादी आकांक्षाओं को शामिल करते हुए नए संविधान को लिखे जाने में असफल रहने के कारण है।

जनवादी लोक आंदोलन का लक्ष्य एक ओर सामाजिक न्याय के आधार पर लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करना और लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध करना था , दूसरी ओरसशस्त्र माओवादी लड़ाकों को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करना था। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2006 के नए पुनर्बहाल किए गए संसद ने नए सिरे से प्राप्त लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता की मजबूती के लिए कुछ उल्लेखनीय निर्णय लिए। उसी प्रकार , संविधान सभा के लिए बहुप्रतीक्षित चुनाव 10 अप्रैल , 2008 को हुआ जिसमें 601 सदस्यों वाली संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा ने नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति एवं इसे एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किए जाने सहित कई ऐतिहासिक निर्णय लिए , इस प्रकार देश में 10 वर्ष से चल रहे सशस्त्र माओवादी विद्रोह की समाप्ति और शांति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। नई चुनी गयी संविधान सभा नेपाल के इतिहास में सबसे समावेशी मंचों में से एक है जिसमें विभिन्न जातीय समूहों के सदस्यों, दलितों और महिलाओं को अधिकाधिक संख्या में शामिल किया गया। 33 प्रतिशत से अधिक सीटों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया। उसी प्रकार दलितों , मधेशियों और अन्य अल्पसंख्यक समूह पर्याप्त संख्या में शामिल हो पाए। नेपाल के इतिहास में यह पहली बार है कि लैंगिक, जातीयता, वर्ग, संस्कृति, जाति, धर्म और पिछड़े क्षेत्रों के संदर्भ में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों को देश के सबसे उंची निर्णय लेने वाले निकाय में सीट पाने की अनुमति प्राप्त हुई। लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने , अपवर्जन प्रथाओं को समाप्त करने और लोगों के लिए समान अधिकार और अवसर प्रदान करने के लिए शासन व्यवस्था की इस एकल प्रणाली को संघीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था।

तथापि नव निर्वाचित संविधान सभा जिसने नेपाल वासियों में बहुत अधिक आशा और आकांक्षाओं को उत्पन्न किया था , अपने समनुदेशित कार्य को पूरा करने में असफल रही और नए संविधान को तैयार किए बिना ही भंग हो गयी। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेदऔर कई

संगत मुद्दों पर एकमत होने में उनकी अक्षमता , और उनके बीच लचीलेपन की कमी के कारण अंतत: संविधान सभा भंग हो गयी। प्रथम संविधान सभा के भंग होने से देश और भी अनिश्चितता और कठिनाइयों में घिर गया। हलांकि , प्रमुख दलों ने पुन: धारणीय बातचीत की और अब वे समझौते पर पहुंचे हैं कि इस वर्तमान राजनीतिक संकट को समाप्त करने का एकमात्र उचित तरीका एक और संविधान सभा के लिए चुनाव कराना है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दल अंतरिम संविधान को संशोधित करने के लिए सहमत हुए और साथ हीं नेपाल के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक नया दल विहीन सरकार का गठन किया। नव गठित सरकार ने द्वितीय संविधान सभा के लिए चुनाव की तिथि के रूप में 19 नवम्बर , 2013 की तिथि की घोषणा की है।

चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद सरकार और राजनीतिक दलों के लिए इस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से और भयमुक्त वातावरण में निर्धारित तिथि को चुनाव कराना है। सरकार और प्रमुख दलों की जिम्मेदारी इस चुनाव के लिए अनुकूल माहौल सृजित करना है। उन्हें वार्ता और समझौतों के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में असंतुष्ट दलों और समूहों को लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मैं आश्वस्त हूं कि आपके सामूहिक प्रयायों से हम उनका विश्वास जीत सकते हैं और आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं ; और इससे इस चुनाव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। घोषित तिथि पर चुनाव कराने से लोकतंत्र को संस्थागत करने और देश के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान बनाने में सहायता मिलेगी।

यद्यपि कई संगत मुद्दों पर प्रमुख राजनीतिक दलों में पिछली संविधान सभा में उभरे मतभेद वही हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि पिछली संविधान सभा के अपने कार्यों को पूरा किए बिना ही भंग होने से हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। इस संदर्भ में मैं यहां यह जोड़ना चाहता हूं कि पिछली संविधान सभा ने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। उसने कुछ निर्णय लिए , कुछ समझौते हुए और कुछ समझ बनी है। मेरा दल इसे दृढ़ता से महसूस करता है कि हमें लिए गए उन निर्णयों, समझौतों और समझ को अक्षुण्ण बनाए रखना है। इससे एक निर्धारित समय-सीमा में संविधान के प्रारूप को तैयार करने में अगले संविधान सभा को बहुत सहायता प्राप्त होगी।

मेरी पार्टी , कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल (यूएमएल) का दृढ़ विश्वास है कि केवल चुनाव आयोजित करने से हम नेपाल में दीर्घकालिक शांति और लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं। हम भी पूरी तरह आश्वस्त हैं कि यही एक माध्यम है जिससे हम देश के अस्थिर राजनीतिक माहौल समाप्त हो सकता है और अति आवश्यक आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो सकता है। मुझे यह भी विश्वास है कि राजनीतिक दलों के बीच

नियमित परामर्श, समझव सामंजस्य की प्रक्रिया के माध्यम से ही हम इन कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए, राष्ट्रीय राजनीति व विकास संबंधी मुद्दों पर व्यापक समझ तथा राजनीतिक दलों व नेताओं के बीच परस्पर विश्वास, विशेषकर देश की प्रमुख दलों में परस्पर विश्वास समय की मांग है। केवल इसी माध्यम से हम कुछ सबसे संवेदनशील और विवादित मुद्दों का समाधान कर सकते हैं और कुछ जोखिमों के बावजूद स्वतंत्र और शांतिपूर्ण वातावरण में निर्धारित तिथि को चुनाव करा सकते हैं।

यह हमारा विचार है कि भावी सरकार को सरकारी , निजी और सहकारी क्षेत्रों जो हमारे समाज के मुख्य उपक्रम हैं , की भूमिकाओं में बढ़ोतरी कर आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ; और उनके उचित संघटन से अपेक्षित आर्थिक विकास और धारणीय विकास सुनिश्चित होगा। हमें आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए किंतु उतना ही ध्यान इस अर्थव्यवस्था के वितरण पहलुओं के समाधान पर भी देना चाहिए। नए संविधान में लोगों की प्रगतिशील कार्यसूची को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ , शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय, खाद्य सुरक्षा, पेयजल और रोजगार के क्षेत्रों में लोगों के कुछ मूलभूत अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए। नेपाली संदर्भ में एक विशेष विचार किया जाना होता है क्योंकि नेपाल एक दशक से अधिक समय से हिंसात्मक विवाद से गुजरा है और अभी भी सामाजिक अंतर्विरोध के कई रूपों के साथ संघर्ष चल रहा है। थोड़े समय में लोगों की समृद्धि के लिए समान वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हेतु समानांतर अभियान अनिवार्य है। इससे हमारा शताब्दी पुराना सामाजिक सामंजस्य सुनिश्चित हो सकता है एवं और मजबूत हो सकता है। अभी भी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो कुछ यथा स्थिति वाले दृष्टिकोण का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं जो हमारे समाज की दीर्घकालिक शांति, लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं है। इस समग्र प्रक्रिया में न केवल परामर्श की प्रक्रिया को मजबूत करना और राजनीतिक सामंजस्य बनाना आवश्यक होगा बल्कि भारत , जिससे नेपाल का दीर्घकाल से ही निकट संबंध है , जैसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों से उदार सहायता जारी रहना भी आवश्यक है।

हमें सुरक्षा एजेंसियों , नौकरशाही और राज्य के अन्य अंगों जैसे पेशेवर रूप से कमजोर राजकीय ढ़ांचों को मजबूत करना है। उन्हें योजना बनाने व प्राथमिकताएं तय करने तथा लोगों के जीवन में सुधार लाने के कार्य में किया जाना चाहिए। यदि सुरक्षा की स्थिति स्थिर हो और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार संविधान सभा के चुनाव , नए संविधान का प्रारूप तैयार करने , शांति स्थापित करने , आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में राष्ट्रीय सामूहिक कार्य हेतु सामाजिक शक्तियों को एक जुट कर सकती है , तो हम उन क्षेत्रों में वास्तविक प्रगति कर सकते हैं।

चूंकि अभी भी हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक - आर्थिक मुद्दों पर मुख्य राजनीतिक दलों के बीच राष्ट्रीय सामंजस्य बनाना समय की मांग है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम सभी को ईमानदार और समर्पित होना पड़ेगा। नेपाल को शांतिपूर्ण, स्थिर, लोकतांत्रिक, समृद्ध व सद्भावनापूर्ण समाज के रूप बदलना और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को शामिल करते हुए एक लोकतांत्रिक संविधान को तैयार करना और उसे प्रख्यापित करना हमारे लिए एक बड़ा कार्य है। इस बड़ी प्रतिस्पर्धी दुनिया में ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए हमें देश के भीतर एक होकर रहना चाहिए और साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। और ऐसे प्रयासों को पूरा करने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय मित्रों विशेषकर भारत जैसे हमारे पड़ोसी देशों से सहयोग और पूर्ण एकता चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

***